1	2	3
12.	Telugu	32,95,614
13.	Kannada	28,39,710
14.	Sanskrit	14,381
15.	Sindhi	4,44,261
16.	Nepali	1,37,079
17.	Khasi	23,910
18.	Konkani	9,063
19.	Mizo	61,015
		22,32,65,609

चलचित्र अधिनियम, 1952 का उल्लंघन

963 श्री ईश दत्त यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पक्ष तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 का उल्लंघन करने पर कुल कितने व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है;

(ख) इस संबंध में वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या यह भी सच है कि चलचित्र अधिनियम का पालन सख्ती से नहीं किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 7 में फिल्मों के प्रमाणीकरण के संबंध में अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन पर दण्ड निर्धारित है। इन दण्डात्मक उपबंधों को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों का है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उक्त अधिनियम के दण्डात्मक उपबंधों को सख्ती से लागू करने और अपराधियों से स्पष्टीकरण मांगने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है। तथापि, उक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए जिन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनकी संख्या के बारे में सूचना मंत्रालय में केन्द्रीय तौर पर संकलित रूप में नहीं रखी जाती है क्योंकि अधिनियम के दण्डात्मक उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित मसले बुनियादी तौर पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से संबंधित होते हैं।

National Poliey for protecting interesr of media, persons

964. MISS SAROJ KHAPARDE : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a National Policy for the media persons so that their professional interest* could be protected in a better way to enable the journalists to report and publish news and comments without pressure or favour:

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not. the reasons therefor ?

"THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P, SINGH
DEO) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Press in our country enjoys full freedom and there is an institution viz., "Press Council of India" to protect the professional interest of media persons.